

संपादकीय

होर्मुज जलमार्ग से वैश्विक जरूरत के बीस से पच्चीस प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत भी उन देशों में शामिल है, जिनकी खासी निर्भरता वहां से आने वाले ऊर्जा स्रोतों पर है।ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद समूचे मध्यपूर्व के इलाके में जैसे जटिल हालात पैदा हुए हैं, उसका स्वाभाविक असर वैश्विक पैमाने पर ऊर्जा की आपूर्ति पर पड़ा। हालांकि जब दोनों पक्षों के बीच चौदह दिनों के युद्धविराम

की घोषणा हुई थी, तब उम्मीद जगी थी कि अब शायद ईरान होर्मुज जलमार्ग को भी खोल दे और कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बहाल हो। मगर उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता नाकाम रही और इसी के साथ होर्मुज जलमार्ग की बहाली की उम्मीद एक बार फिर मंद पड़ गई।आज हालात यह है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति शृंखला बाधित होने का जिन देशों पर ज्यादा असर पड़ा है, वे अब ऊर्जा के

होर्मुज संकट के बीच बढ़ी ऊर्जा चिंता, विकल्पों की तलाश में भारत की नई रणनीति

वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग बाधित होने के बाद तेल और गैस की व्यापक कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि रसोई गैस के विकल्प के रूप में बायोगैस सहित अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को हर हाल में बढ़ावा दिया जाए।दरअसल, होर्मुज जलमार्ग से वैश्विक जरूरत के बीस से पच्चीस प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत भी उन देशों में

शामिल है, जिनकी खासी निर्भरता वहां से आने वाले ऊर्जा स्रोतों पर है। यही वजह है कि ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई है और उसके बाद अमेरिका ने नाकाबंदी की, तब से देश घरेलू गैस और पेट्रोल-डीजल की व्यापक कमी का सामना कर रहा है। यों तो इस बीच सरकार ने रूस से तेल खरीद के रास्ते तैयार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रुख की वजह से उसमें भी कई अड़चनें पेश आ रही

हैं। ऐसे में फिलहाल सबसे बेहतर उपाय यही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ढांचा तैयार किया जाए। इस लिहाज से देखें तो देश में बायोगैस सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों की जमीन मजबूत होती है, तो यह न केवल तात्कालिक स्तर पर समस्या का सामना करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह दूरगामी स्तर पर देश के व्यापक हित में होगा।पश्चिम एशिया में एक ओर अमेरिका के

रुख तो दूसरी ओर ईरान के जवाबी रवैये की वजह से न केवल भारत, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने संकट धीरे-धीरे गहरा रहा है। शायद इसीलिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक ने दुनिया को यह चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह और बिना किसी शर्त के जल्द नहीं खुला, तो दुनिया जल्दी ही ‘रेड जोन’ में प्रवेश कर सकती है, जहां तेल आपूर्ति सामान्य मांग को भी संभालने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगी।

आज असली परीक्षा इस देश को चलाने वाले शासकों की साख, नीयत और उनके इकबाल की है। जिस समाज में शिक्षा और न्याय केवल एक औपचारिकता बन जाएं, वहां देश का भविष्य केवल एक संयोग बनकर रह जाता है, कोई गौरवशाली नियति नहीं। देश में जब भी किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है, तो जांच के आदेश के बाद ‘मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी’ और ‘दोबारा परीक्षा की तारीख’ जैसी बातों के शोर-शराबे के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिप जाता है। नीट परीक्षा के इस अंतहीन तमाशे और बार-बार होने वाले प्रश्नपत्र लीक ने भारत में एक नए किस्म के पलायन को जन्म दे दिया है। अब तक देश का युवा डॉक्टर बनने के बाद विदेश जाता था।

पेपर लीक ने तोड़ा छात्रों का भरोसा, अब विदेश जा रहे मेधावी युवा

(मणिमाला शर्मा)

अब इस परीक्षा तंत्र से तंग आकर देश के मेधावी विद्यार्थी बारहवीं पास करते ही भारत छोड़ रहे हैं।

वे एक अनिश्चित और भ्रष्ट दलदल में अपनी उम्र के कीमती साल बर्बाद नहीं करना चाहते। नीट का प्रश्नपत्र लीक होना सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, बल्कि यह देश के उस भरोसे का टूटना है, जो एक विद्यार्थी अपनी व्यवस्था पर करता है। देश के भीतर चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का दम भरने वाला शासन क्या इस कड़वे सच पर आत्ममंथन करने का साहस दिखाएगा कि उसने अपनी ही नई पीढ़ी को इस कदर बेगाना और विरक्त कर दिया है?

इस चौंकाने वाले पलायन, जनता के आक्रोश और व्यवस्था की गिरती साख को बचाने के लिए ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024’ पूरे देश में लागू किया गया था। कागज पर यह कानून बेहद सख्त दिखाई देता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे नीति-नियंताओं से यह पूछा जाना जरूरी है कि यह कानून लागू होने के बाद भी क्या परीक्षा माफिया और उन्हे राजनीतिक संरक्षण देने वालों में कोई वास्तविक खौफ पैदा हुआ है? क्या इस तथाकथित कड़े कानून के तहत अब तक किसी एक भी बड़े शिक्षा माफिया, सांठगांठ करने वाले शोष अधिकारियों या प्रश्नपत्र बेचने वाले संगठित गिरोह के सरगना को ऐसी सजा मिली है, जो एक नजीर बन सके?

शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का अभाव

सच यह है कि जब तक कानून केवल फाइलों की शोभा बढ़ाते हैं, तब तक यह पूरी कवायद केवल एक प्रशासनिक दिखावे और जनता के गुस्से को शांत करने वाला ‘प्रयोजित प्रबंधन’ ही साबित होती है। परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में 1०1 अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशों की थीं। मगर विरंडेना यह है कि उन सिफारिशों को टंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। इस तरह की नीतिगत और प्रशासनिक विफलता की सबसे कारुणिक कीमत उस मध्यवर्गीय परिवार को चुकानी पड़ती है, जिसके

चाहिए, जिसने अपनी पुरश्चैनी जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ इसलिए बेच दिया, ताकि उसका बच्चा समाज में सिर उठाकर कह सके कि वह ‘डॉक्टर’ बनने जा रहा है। भारत का मेडिकल कोचिंग क्षेत्र स्कूलों को ‘डमी’ संस्थाओं में बदलकर एक समांत, अनियंत्रित और शोषक व्यवस्था बन चुका है। ग्यारहवीं और बारहवीं की सामान्य, जीवंत स्कूली जिंदगी को खत्म करके हमने एक पूरी पीढ़ी के सामाजिक और मानसिक विकास को बलि चढ़ा दी है। हमने बच्चों को संवेदनशील ईंसान बनाने के बजाय केवल एक ‘बहुवैकल्पिक प्रश्नपत्र’ को हल करने वाले और रैंक की अंधी दौड़ में दौड़ने वाले रोबोट में तब्दील कर दिया है। सबसे ज्यादा मार उन गरीब

आधात, व्यवस्था के प्रति उपजे गहरे आक्रोश, अवसाद और ‘बिकाऊ तंत्र’ के साप में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू करेगा, वह भविष्य में मरीजों के प्रति अपना कैसा दृष्टिकोण रखेगा? जब एक पूरी पीढ़ी यह सीखकर बड़ी होगी कि रसूख, पैसा और पहुंच ही अंतिम सत्य हैं, तो उस डॉक्टर से एक ‘सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील मसीहा’ बनने की उम्मीद करना ही बेमानी है।

जिसने खुद तंत्र के हाथों आर्थिक और मानसिक शोषण झेला हो, वह डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले अपनी उस पुंजी और उस प्रताड़ना का ब्याज वसूलने की कोशिश करेगा। यह चक्र देश के स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से संवेदनहीन, अनैतिक और व्यावसायिक बनाने की ओर धकेलेगा, जिसकी अंतिम परिणति गरीब

एक ही परीक्षा पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए साल में अनेक प्रयास और बारहवीं के अंकों के वैकल्पिक मूल्यांकन जैसे विकल्पों पर नीतिगत स्तर पर गंभीरता से विचार करना होगा। साथ ही, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को वर्तमान ढांचे से मुक्त कर संसद के अधीन एक स्वायत्त और पूरी तरह जवाबदेह संस्था बनाना होगा, जैसा कि देश के कई शिक्षाविद मांग कर रहे हैं। आज असली परीक्षा इस देश को चलाने वाले शासकों की साख, नीयत और उनके इकबाल की है। जिस समाज में शिक्षा और न्याय केवल एक औपचारिकता बन जाएं, वहां देश का भविष्य केवल एक संयोग बनकर रह जाता है, कोई गौरवशाली नियति नहीं। (यह लेखक के अपने विचार हैं)।

प्रधानमंत्री के रूप में श्रीनरेंद्र मोदी के बारह वर्ष : बिना अवकाश लिये निरंतर कार्य करने का कीर्तिमान

आत्मशक्ति और आंतरिक ऊर्जा जागरण से ही संभव

रमेश शर्मा

प्रधानमंत्री के रूप में श्रीनरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के बारह वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। उनका यह कार्यकाल कार्यशैली, नीति निर्णयों की विशिष्टता से ही नहीं कीर्तिमानों और नवाचारों से भरा है। ऐसे नवाचार जिनकी चर्चा वैश्विक स्तर पर हुई। बिना कोई अवकाश लिये निरन्तर सोलह से अठारह घंटे काम करने वाले संसार के अकेले राजनेता हैं उनकी यह विशेषता उन्हें एक विशिष्ट प्रज्ञा पुरुष की पंक्ति में प्रतिष्ठित करती है।

श्रीनरेंद्र मोदी इससे पहले गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। सत्ता प्रमुख रहते हुये इन दोनों कार्य दायित्व की कुल अवधि चौबीस वर्ष से अधिक सत्ता प्रमुख रहने का कीर्तिमान सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमन् कर्ण चिमलिंग के नाम था। वे ८930 दिनों तक लगातार सत्ता प्रमुख रहे थे। जिसे मोदीजी ने पीछे छोड़ दिया है। और वे निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में सबसे अधिक दिन सत्ता का नेतृत्व करने के इस कीर्तिमान के साथ

श्रीनरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। वे संसार के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपने पद दायित्व की इतनी लंबी

अवधि में कोई अवकाश नहीं लिया। न उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते कोई अवकाश लिया था और न अब प्रधानमंत्री रहते हुये कोई अवकाश लिया। उनकी विदेश यात्राएँ भी भारत राष्ट्र के हितों के उद्देश्य पूर्ति केलिये हुई हैं।

पिछले दिनों सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के उत्तर में यह तथ्य सामने आया। जिसकी चर्चा संपूर्ण विश्व के मीडिया जगत में हुई। बिना कोई अवकाश लिये निरन्तर कार्य करने की उनकी क्षमता की एक और विशेषता है। वह है प्रतिदिन अधिकतम समय तक कार्य करने की। वे प्रतिदिन अधिक घंटों तक कार्य करने वाले विश्व के अकेले राजनेता हैं। सामाजिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक, अथवा सार्वजनिक कार्यों में वे प्रतिदिन सोलह से अठारह घंटे तक व्यस्त रहकर मोदीजी 24×7 सक्रिय रहने के लिए प्रसिद्ध हैं।

उनके पद दायित्व के इन दोनों कीर्तिमानों में उनके नवाचार भी अनूठे हैं। वे अपने साहस, क्षमता, दृढ़ता, दूरदृष्टि और भारत राष्ट्र के साँस्कृतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा केलिये भी जाने जाते हैं। वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते और न लक्ष्य से कभी विचलित होते हैं। उनका व्यक्तित्व असाधारण है इसलिये उनके कार्य और कार्यशैली भी असाधारण है। असाधारण कार्यों के लिये प्रकृति सदैव असाधारण व्यक्तित्व को ही निमित्त बनाती है। भारतीय वाङ्मय में वैदिक ऋषियों की दिनचर्या पढ़ने को मिलती है। ऋषियों के आठों प्रहर सतत सक्रियता में व्यतीत होते थे। पूरा जीवन साधना, अध्ययन, मनन, चिंतन, नूतन अनुसंधान और समाज निर्माण केलिये बौद्धिक प्रबोधनों में बीताता था। ऋषि परंपरा के अनुरूप ही

लेखन प्रवचन का जो विशाल भंडार स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का उपलब्ध है वह भी अद्वितीय है। इन सबका चिंतन और कार्य असाधारण हैं। यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक हो कि सीमित आयु सीमा में यह कैसे संभव होता

है। असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तित्व भी असाधारण होते हैं। जिन्हें प्रकृति विशिष्ट कार्यों का निमित्त बनाती है।

ऋषि परंपरा से लेकर स्वामी विवेकानंद इस असाधारण कार्यशैली की झलक भारत के प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी की कार्यशैली और कार्यक्षमता में मिलती है। मोदीजी की दिनचर्या, संकल्पशीलता, ध्येयनिष्ठा, दूरदर्शी चिंतन, सत्य पर अडिगता और निरन्तरता असाधारण है। उन्होंने कुछ ऐसे नवाचार किये, कीर्तिमान बनाये जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी।

बालपन से लेकर वर्तमान काल तक श्रीनरेंद्र मोदी के कार्य और कार्यशैली दोनों विशिष्ट रहे। वे जहाँ भी रहे, उनके हाथ में जो काम रहा वहाँ उन्होंने एक नये इतिहास की रचना की है। उनकी कार्यशैली की तीन बड़ी विशेषताएँ हैं। पहली वे संकल्प सुनिश्चित कर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। दूसरी यह कि वे किसी भी आलोचना और राजनैतिक हमले से विचलित नहीं होते। और तीसरी सामने आई चुनौती को स्वीकार करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद दायित्व से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली में ये तीनों विशिष्टताएँ बहुत स्पष्ट रहीं हैं। श्रीनरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह भी है कि वे अपने ऊपर फेंके गये पत्थरों की चुनौती स्वीकार करते हैं और उन्हीं से अपनी सुरक्षा दीवार पर भी बनाते हैं। मोदीजी ने

दिसम्बर 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद दायित्व संभाला था। तब से आज तक उन पर जितने राजनैतिक हमले हुये उतने किसी राजनेता पर नहीं। ऐसे हमले केवल भारत में ही नहीं हुये अपितु दुनियाँ के कये देशों में उनके विरुद्ध योजनापूर्वक वातावरण बनाया गया। इस आलोचना के दबाव में ही एक बार अमेरिका ने उनका बीजा निरस्त कर दिया था। उन दिनों मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अमेरिका की इस पर कार्यवाही पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारा और जब वे प्रधानमंत्री बने, अमेरिका के आमंत्रण पर अमेरिका गये तो उनके सम्मान में व्हाइट हाँउस में ‘डिनर’ का आयोजन किया गया। अमेरिका के इतिहास में यह व्हाइट हाउस का सबसे भव्य डिनर था। इसकी व्यापकता की झलक रहती है। मोदीजी देश के पहले ऐसे गैर मदिरा तो दूर अण्डे तक नहीं थे।

मोदीजी ने सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक और प्रशासनिक निर्णयों के नवाचार में भी कुछऐसे कीर्तिमान बनाये हैं जिन्हें तोड़ना आने वाले किसी राजनेता के लिये संभव नहीं लगता। उन्होंने वर्ष 2014 में संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करके अपना संसदीय जीवन आरंभ किया था। स्वतंत्रता के इतिहास में सांसद की सीढ़ियों को प्रणाम करके संसद में प्रवेश करने वाले वे पहले राजनेता हैं। मोदीजी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। उनसे पहले भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का जन्म स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। वे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद दायित्व संभालने से पहले भारत के अधिकांश जिला केन्द्रों की यात्रा कर ली थी। इसीलिये उनके निर्णयों भारत की विविधता, विशेषता और व्यापकता की झलक रहती है। मोदीजी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में लगातार तीन बार बहुमत मिला और सरकार बनी। उनके प्रधानमंत्रीत्व कार्यकाल में कुछ ऐसे निर्णय भी हुये जिनकी किसी को कल्पना नहीं, ये कार्य एक

प्रकार से किसी स्व्न के आकार लेने जैसे हैं इनमें कश्मीर से धारा 370 का समाप्ति, राम जन्मस्थान अयोध्या में रामजी की प्राण प्रप्तिष्ठा होना, पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक, आरंभशरन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ढेर किये, कोरोना महामारी में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण, निशुल्क टीकाकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पड़ौसी देशों से धार्मिक आधर पर प्रताडित नागरिकों को भारत में शरण देने का कानून बनाना, किसान सम्मान निधि, उज्जवला योजना, जनधन योजना, स्वदेशी उत्पाद को प्राथमिकता, महिला, युवा किसान और गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ बिना किसी भेदभाव के ‘सबका साथ सबका विकास’ का संकल्प लेकर भारत की अर्थ व्यवस्था का उन्नयन। वे इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदीजी की दृढ़ता का इतना बड़ा उदाहरण विश्व में कहीं मिलेगा कि अमेरिकी टैरिफ धमकी के बाद भी भारत अपनी नीतियों पर अडिग रहा और अमेरिका को झुकना पड़ा। मोदीजी जो कदम उठाते हैं दूरदृष्टि के साथ उठाते हैं। नारी सम्मान की दिशा में महिला आरक्षण विधेयक पर निचार केलिये भले अप्रैल 2026 में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया लेकिन इसका लक्ष्य उन्होंने बहुत पहले सुनिश्चित कर लिया था। संसद के नये भवन निर्माण का आकार इसे ध्यान रखकर ही तैयार किया गया था। इस भवन की नींव 2020 में रखी गई थी। मोदीजी ने अपने सार्वजनिक जीवन की यात्रा भारत राष्ट्र के परम् वैभव का स्वप्न संजोकर आरंभ की थी। वे इसे कभी नहीं भूलें। भारत को परम् वैभव के स्थान पर प्रतिष्ठित करने केलिये उन्होंने वर्ष 2047 का लक्ष्य निश्चित किया है। इस दिशा भारत अभी विश्व की चौथी शक्ति के स्थान पर पहुँचा है और तीसरे क्रम पर आने के समीप है। आशा की जा रही है कि वर्ष 2035 तक भारत विश्व की प्रथम अर्थ शक्ति बनेगा और वर्ष 2047 तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र।

